

प्रेषक,

सी० एस० नपलच्याल,
सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री विजय बहुगुणा,
मा० पूर्व मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

दिनांक : 29, नवम्बर, 2016।

विषय :- मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मा० भूतपूर्व मुख्यमंत्रीगणों को आवंटित शासकीय आवासों के अध्यारोपित किराये के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1333/xxxii-2-2016-3(31)/2015, दि० 17, अक्टूबर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको आवंटित शासकीय आवास को रिक्त करने तथा आवास के अध्यारोपित किराये की आगणित राशि की वसूली हेतु पृथक से सूचित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया था।

2- तदक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य की भूतपूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान आवंटन नियमावली-1997, जिसके अनुरूप आपको शासकीय आवास आवंटित है, के प्रस्तर-05 की व्यवस्थानुसार, शासनादेश सं०-2417/2004, दि० 16.11.2004 द्वारा निर्धारित लिविंग एरिया के आधार पर फ्लैट रेंट के अनुसार आपके पूर्व मुख्यमंत्रित्वकाल की अवधि में आवंटित शासकीय आवासों का अध्यारोपित किराया निम्नवत् है :-

A आवासीय पता	B आवास का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	C आवास में अध्यासन अवधि का विवरण	D आवास में कुल अध्यासन अवधि	E शासनादेशानुसार लिविंग एरिया के आधार पर निर्धारित फ्लैट रेंट (रु० में)	F कुल अध्यारोपित किराया (रु० में) F = D × E
सर्किट हाउस, पुराना भवन, बीजापुर राज्य अतिथि गृह, देहरादून।	508.36	03, फरवरी, 2014 से 12, फरवरी, 2014	10 दिन	1,200.00/माह	400.00
		16, जून, 2015 से 31, अक्टूबर, 2016 तक	01 वर्ष 04 माह 15 दिन		19,800.00
सर्किट हाउस ऐनेक्सी, देहरादून।	363.65	13, फरवरी, 2014 से 15, जून, 2015 तक	01 वर्ष 04 माह 01 दिन	1,200.00/माह	19,240.00
कुल धनराशि					39,440.00

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आवंटित शासकीय आवासों के अध्यारोपित किराये की राशि का भुगतान मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी० एस० नपलच्याल)
सचिव।

संख्या: 1476/xxxii-2-2016-3(31)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन / मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 2- सचिव, विधानसभा सचिवालय, /सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/राज्य सम्पत्ति अनु-01 एवं 03/गोपन(मंत्रिपरिषद्) विभाग/सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अध्यारोपित किराये की राशि को प्राप्त करते हुए, नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें/एन०आई०सी०, देहरादून/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

28/11/16

(विनय शंकर पाण्डेय)

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

